

स्वामित्व योजना

ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए

ग्रामीण नागरिकों को योजना से लाभ

- संपत्ति के मालिक को मालिकाना हक प्राप्त होगा
- मालिकाना हक से ग्रामवासी ऋण आदि लेने में सक्षम होंगे
- गांव के आबादी क्षेत्र का रिकार्ड पंचायतों को प्रदान कर सकेंगे
- संपत्ति के स्पष्ट आंकलन एवं स्वामित्व का निर्धारण होने से उनके मूल्य में भी वृद्धि होगी



पंचायतों को योजना से लाभ

- पंचायतों द्वारा कर संग्रह करना संभव होगा
- आमदनी से ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधा दे पायेंगी
- गांव का सटीक मानचित्र व रिकार्ड उपलब्ध होगा
- रिकार्ड का उपयोग कर वसूली, भवन निर्माण हेतु परमिट जारी करने, अवैध कब्जा समाप्त करने में किया जायेगा



क्रियान्वयन विभाग:
राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उ०प्र०
पंचायती राज विभाग, उ०प्र० द्वारा जनहित में जारी।